भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1474

29.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

दुर्लभ अर्थ मैगनेट के घेरलू उत्पादन को बढ़ावा देना

1474. **श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ अर्थ मैगनेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख प्रोत्साहन, नीतिगत उपाय और साझेदारी मॉडल क्या हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र में किसी औद्योगिक क्षेत्र या क्लस्टर की पहचान की गई है और यदि नहीं, तो जलगाँव जैसे संभावना वाले तैयार क्षेत्रों को बाहर रखने के क्या कारण हैं, जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे जंक्शनों और हवाई अड्डों से निकटता के कारण बेहतर संपर्क साधन है;

(ग) वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने और पारंपरिक देशों से दुर्लभ मृदा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए हितधारकों के साथ सरकार की बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत की दुर्भल अर्थ मैगनेट पहल के संबंध में इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटो घटक उद्योग से प्राप्त प्रतिक्रिया और जानकारी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पहल के तहत की गई प्रारंभिक प्रगति का ब्यौरा क्या है और निवेश, उत्पादन क्षमता या अनुसंधान एवं विकास सफलता के माध्यम से आयात पर निर्भरता कम होने का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): नीति आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अंतर्गत इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) ने "दुर्लभ मृदा तत्वों का उपयोग करके डाउनस्ट्रीम उद्योग की स्थापना हेतु प्रोत्साहन ढाँचे" पर एक दस्तावेज़ तैयार किया है।

(ग) और (घ): भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के स्वदेशी उत्पादन की स्थिति का आकलन करने के लिए अनुसंधान संगठनों और इलेक्ट्रिक वाहनों एवं ऑटो घटकों

के विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के साथ 26.09.2024 और 17.06.2025 को दो परामर्श बैठकें आयोजित कीं।

इसके अलावा, वाणिज्य विभाग ने हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों से युक्त एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन अध्ययन समूह की स्थापना की है। साथ ही, विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूटीओएस) में आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन अध्ययन समूह के मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

भारत ने नवंबर, 2023 में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ़), जो इस क्षेत्र का 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है, के तहत आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करना है। यह समझौता 24 फ़रवरी, 2024 को लागू हुआ। इस समझौते के तहत, एक आपूर्ति श्रृंखला परिषद (एससीसी) की स्थापना की गई है, जिसका अध्यक्ष अमेरिका और उपाध्यक्ष भारत है।

(ङ): परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने देश में विशेष रूप से रक्षा और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग के लिए समारियन-कोबाल्ट चुम्बकों के स्वदेशी उत्पादन हेतु एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) संयंत्र स्थापित किया है।

*****